सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की

विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है।
-हेलेन केलर

मूल्य ₹ 3/-

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK

• वर्षः 11 • अंकः 230 पृष्ठः 8 • लखनऊ, शुक्रवार 26 सितम्बर, 2025

वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय टीम... 7 | पटना से निकलेगी देश की नई... 3 | पीडीए की एकता से घबराई... 2

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की आहट

विपक्ष में बैचेनी, एक सुर में बयान का विरोध

बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का दावा अप्रैल से पहले लग जाएगा बंगाल में राष्ट्रपति शासन

» एसआईआर के जरिये एक करोड़ लोगों के मतदाता सूची से नाम कटने का भी दावा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया है कि अप्रैल से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कालीघाट लौटना पड़ेगा। दिलीप घोष यही नहीं रूके हैं उन्होंने एसआईआर पर भी बेतुकी बात कही है। उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल में एसआईआर से एक करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिये जाएंगे तो ममता बनर्जी की पार्टी अपने आप चुनाव हार जाएगी।

उनका यह बयान बिहार में चल रही राजनीतिक तूफान को और तेज कर सकता है। क्योंकि बिहार मे चुनाव आयोग पर प्रीप्लान तरीके से वोटर्स के नाम काटने का आरोप सियासी दल लगा रहे हैं। दिलीप घोष का यह बयान इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि क्या पहले से टारगेट कर लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाये जाते हैं। दिलीप घोष के इस बयान ने राज्य की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या वास्तव में केंद्र सरकार इतना बड़ा कदम उठा सकती है? क्या किसी राज्य की लोकतांत्रिक सरकार को इतनी आसानी से हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है?

1994

में एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यानी यदि केंद्र बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाता है तो यह मामला सीधे अदालत में चुनौती बन जाएगा।

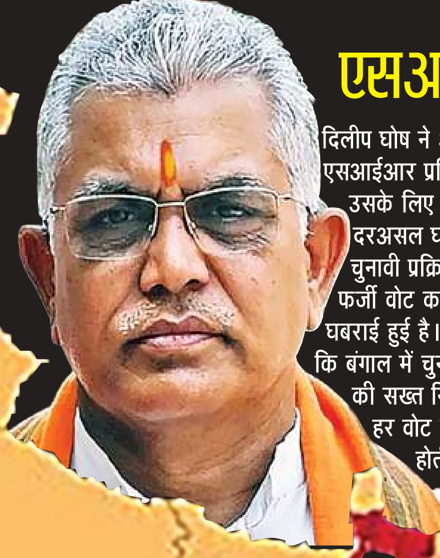

एसआईआर प्रक्रिया, आगे की राजनीति

दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी एसआईआर प्रक्रिया से डरती है और यह उसके लिए करो या मरो का सवाल है। दरअसल घोष यह दिखाना चाहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली रोकने और फर्जी वोट काटने की कार्रवाई से तृणमूल घबराई हुई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बंगाल में चुनाव आयोग और न्यायपालिका की सख्त निगरानी रहती है। हर वोट पर नजर होती है।

ऐसे में करोड़ों वोटों का रद्द होना लगभग असंभव है। यह बयान जनता में असंतोष फैलाने और टीएमसी की छवि पर हमला करने का एक और राजनीतिक प्रयास के तौर पर माना जा रहा है।

कुछ दिन और चलने दीजिए

दिलीप घोष ने कहा कि पितृ पक्ष के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन कर सारे नियम कायदे बदले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूजा हो या न हो इस पर विवाद करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वे जो चाहेंगी करेंगी। उनका अलग पंचांग है इसीलिए ईद पर दो दिन की छुट्टी दी जाती है। उनका अलग कैलेंडर है उन्हें कुछ दिन और चलने दीजिए।

राजनीतिक हथियार या फिर हकीकत

संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की बात सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई मामलों में कह चुका है कि केंद्र सरकार सिर्फ राजनीतिक कारणों से किसी राज्य की सरकार नहीं गिरा सकती। 1994 में एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यानी यदि केंद्र बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाता है तो यह मामला सीधे अदालत में चुनौती बन जाएगा।

बंगाल अभी दीदी के साथ

पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल नई बात नहीं है। लेकिन दिलीप घोष का बयान महज एक राजनीतिक शिगूफा साबित होता दिख रहा है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति शासन लागू करना कठिन है। जनता के बीच ममता बनर्जी का समर्थन अब भी कायम है। भाजपा की बयानबाजी राज्य की राजनीति को गरम तो कर सकती है लेकिन सत्ता का गणित बदलने की स्थिति में नहीं है। बंगाल की जनता ने हमेशा अपने नेता को अंतिम समय तक समर्थन दिया है। और फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि दीदी का किला ढह रहा है।

पीडीए की एकता से घबराई भाजपा : अखिलेश यादव

» सपा प्रमुख बोले- जाति हमारा इमोशनल कनेक्ट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जाति हमारा इमोशनल कनेक्ट है। पिछड़ों को जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है। मंडल कमीशन की प्रस्तावना में ये बात आई कि हम जाति के आधार पर पिछड़े हैं तो हमें आरक्षण मिला है।

उन्होंने कहा कि भाजपा पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) की एकता से घबरा गई है। जबसे हमने अलग-अलग विभागों में पीडीए की तैनाती के आंकड़े जारी किए हैं तब से भाजपा घबरा गई और लोगों को अपमानित कर रही है। अखिलेश यादव लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे जिसमें उन्होंने योगी सरकार के आदेश कि एफआईआर, अरेस्ट वारंट या किसी भी दस्तावेज पर जाति नहीं लिखी जाएगी के आदेश पर जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि हरिजन एक्ट तो जाति पर ही बना है। जिन लोगों ने गंगाजल से मकान को धुलवाया उन पर कार्रवाई हुई क्या? मैं जिस मंदिर में गया था उसके पंडित के मना करने पर भी भाजपा के लोगों ने मंदिर को धुलवाया। उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा क्यों किया? पीडीए को अब समाजवादी पार्टी पर भरोसा है।

भाजपा सरकार में किसान किए जा रहे प्रताड़ित : श्यामलाल पाल

बूथ प्रभारियों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कहा कि वर्तमान सरकार की लचर व्यवस्था के चलते किसान परेशान हैं। उन्हें खाद तक नहीं मिल पा रही। स्वास्थ्य, शिक्षा का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा सरकार सत्ता में रहेगी तब तक गरीब जनता व किसानों को बुनियादी जरूरतों के लिए प्रताड़ित किया जाता रहेगा।

वर्तमान सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत : आरके चौधरी

विशिष्ट अतिथि सांसद आरके चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए वर्तमान सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। 2027 में सपा की सरकार बनाने के लिए बूथ प्रभारियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। सोनू कनौजिया ने बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष एवं सेक्टर प्रभारियों को सम्मानित किया। प्रदेश उपाध्यक्ष सीएल वर्मा, महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह, प्रदेश प्रवक्ता दीपक रंजन श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह यादव, पूर्व प्रत्याशी राजबाला रावत, विजयश्री गौतम व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

किसानों के साथ अन्याय की कीमत पर विकास का समर्थन नहीं

अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग षडयंत्र करते हैं और किसानों से उनकी जमीन जबरदस्ती ले लेते हैं। किसानों से धोखा करने का रास्ता विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। ये लोग जो कानून हैं उन कानून की परवाह ना कर करके, दबाव बनाकर, झूठे मुकदमें लगाकर, जमीन छीनने का काम करते हैं और ये सिलसिला चल रहा है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और जब हमारी सरकार आएगी तो किसानों को सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजा दिया जाएगा। किसानों के साथ अन्याय की कीमत पर विकास को सही नहीं ठहराया जा सकता।

भाजपा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े

अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में भाजपा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विधायक मंच से बोल रहे हैं कि 10 प्रतिशत कमीशन है उस पर बोलेंगे नहीं और हमें क्रीम, पाउडर और शैंपू में उलझा रहे हैं। हम भी बाजार जाएंगे। कहा कि जो लोग ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं उन्हीं से बात की जा रही है। अखिलेश यादव ने सपा में शामिल होने वाले सुधीर चौहान, पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह, विद्यासागर और लालजी भारती (बसपा से आए हैं) का स्वागत किया।

सरयू से संगम तक पदयात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी

» रोजगार और सामाजिक न्याय होगा मुद्दा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरयू से संगम तक पदयात्रा का आयोजन करेगी। यात्रा युवाओं के रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर की जाएगी। यात्रा की शुरुआत सरयू के तट से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्तूबर को होगी और 15 नवंबर को संगम के तट पर समाप्त होगी। इसकी जानकारी आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दी। उन्होंने यात्रा में युवाओं से शामिल होने का आह्वान किया है।

आप सांसद ने कहा कि प्रदेश में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। युवाओं को रोजगार चाहिए लेकिन सरकार नहीं दे पा रही है। पेपर लीक आम हो गया है। वहीं, जातियों के आधार पर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसलिए यात्रा का विषय रोजगार दो सामाजिक न्याय दो रखा गया है। ये पदयात्रा अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगी जो कि 200 किलोमीटर की होगी।

ये बचत उत्सव नहीं चपत उत्सव है : संजय सिंह

आप सांसद ने जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और कहा कि आठ साल तक देश की जनता को लूटा गया। उनसे 127 लाख करोड़ वसूल लिए गए और अब कह रहे हैं कि राहत देंगे। कहा कि ये बचत उत्सव नहीं चपत उत्सव है।

अरविंद केजरीवाल को 10 दिन में मिलेगा सरकारी घर

केंद्र सरकार ने अदालत को दी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 दिनों में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अदालत में यह आश्वासन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया। अदालत में आप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दलील दी कि केजरीवाल को दिया जाने वाला आवास पहले मिले टाइप-7 या टाइप-8 श्रेणी से कमतर नहीं होना चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि यदि उन्हें आवास से असंतोष है तो सरकार से बातचीत करनी होगी। वहीं, एसजी मेहता ने तंज करते हुए कहा, आम आदमी कभी टाइप-8 के लिए नहीं लड़ता। जिस पर मेहरा ने जवाब दिया कि चुनावी नारों का स्थान अदालत नहीं है।

अदालत ने केंद्र के आश्वासन को दर्ज करते हुए कहा कि इस तरह के आवास से जुड़े विवाद केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी समाधान जरूरी है। साथ ही, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि केजरीवाल आवंटन से असंतुष्ट रहते हैं तो वे सरकार से दोबारा अपील कर सकते हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल ने अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया था और फिलहाल वे पार्टी के एक अन्य विधायक के सरकारी मकान में रह रहे हैं।

गैर एनडीए सरकारों ने जनता के लिए खोला खजाना

जम्मू-कश्मीर सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को पांच मरला जमीन देगी : उमर अब्दुल्ला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बाढ़ के कारण बेघर हुए प्रत्येक परिवार को पांच मरला जमीन दी जाएगी ताकि वे दोबारा अपने घर बना सकें। अब्दुल्ला ने कठुआ जिले की बिलावर तहसील के दुग्गन गांव के निवासियों से बातचीत के दौरान यह घोषणा की, जिनके घर और आजीविका हाल ही में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कठुआ और रियासी जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, उनके साथ बनी विधायक रामेश्वर सिंह और गुलाबगढ़ विधायक खुर्शीद अहमद भी थे। अब्दुल्ला ने रियासी के माहौर में भी लोगों से मुलाकात की। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए, अब्दुल्ला ने प्रशासन को समय पर राहत और पुनर्वास उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ''वर्ष 2025 जम्मू-कश्मीर में भारी तबाही लेकर आया है क्योंकि मार्च-अप्रैल में सूखे से लेकर अगस्त-सितंबर में लगातार बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन तक का सामना करना पड़ा है। कठुआ से कुपवाड़ा तक, अभूतपूर्व नुकसान हुआ है।' अब्दुल्ला ने तबाही को लेकर कहा कि मूसलाधार बारिश से 350 से अधिक पुल, लगभग 2000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है, इसके अलावा खड़ी फसलें बह गईं और सरकारी तथा निजी दोनों संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, 'पुनर्वास चुनौतियों की व्यापकता को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर केंद्र सरकार से एक व्यापक राहत पैकेज की उम्मीद कर रहा है।

स्टालिन, रेड्डी ने छात्रों के लिए 1,000 रुपये की मासिक सहायता योजना का किया उद्घाटन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 1,000 रुपये की मासिक सहायता योजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य प्रथम वर्ष के स्नातक छात्रों को लाभान्वित करना है। राज्य सरकार के एक शिक्षा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार तेलंगाना सरकार की अच्छी योजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है और उन्होंने इसे ''बेहतर विकास की राजनीति'' बताया। स्टालिन ने बताया कि तमिलनाडु की तरह, तेलंगाना में भी महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा योजना है। रेड्डी ने कहा कि उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की 'नाश्ता योजना' से प्रेरणा मिली है और उन्होंने इसे दिल को छू लेने वाला बताया क्योंकि यह सबसे गरीब बच्चों की मदद करती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष से नाश्ता योजना लागू करेगी। रेड्डी ने कहा कि पूरे देश को तमिलनाडु की शिक्षा पहल का अनुकरण करना चाहिए। सरकार के अनुसार, कॉलेज जाने वाली छात्राओं और छात्रों के लिए क्रमशः 'पुधुमाई पेन' और 'तमिल पुधलवन' योजनाओं से इस वर्ष 2,65,318 नये लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्यों को गिनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राज्य सरकार की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।

धान के किसानों को बोनस दे सैनी सरकार : हुड्डा

» बोले कांग्रेस नेता 3100 के वादे को पूरा करे भाजपा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, भाजपा सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। सरकार ने 22 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की घोषणा की थी लेकिन अभी शुरू नहीं हो रही है। किसान मंडियों में खरीद एजेंसियों का इंतजार कर रहे हैं।

खरीद शुरू न होने से किसान निजी एजेंसियों के हाथों लुटने को मजबूर हैं। एकाध जगह धान की खरीद में प्रति क्विंटल 150 से 200 रुपये तक का कट लगाया जा रहा है जबकि किसान पहले ही बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार बोनस देकर किसानों की मदद करे। मंडियों में धान, बाजरा और कपास की आवक शुरू हो गई है लेकिन सरकारी खरीद नहीं होने के चलते किसानों को एमएसपी से 300-400 कम रेट पर धान, करीब 600 रुपये कम रेट पर बाजरा और करीब दो हजार कम दाम पर अपनी कपास बेचनी पड़ रही है। भाजपा ने चुनाव से पहले धान का मूल्य 3100 प्रति क्विंटल देने का वादा किया था।

पटना से मिलेगी देश को नई सीख

अगले महीने चुनावों की तारीखों का हो सकता है ऐलान

- सभी सियासी दलों ने कसी कमर
- बिहार विधानसभा चुनाव में सनातनी राजनीति का भी होगा शंखनाद
- शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लड़ेंगे सभी सीटों पर चुनाव
- औवेसी व शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आमने सामने

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। चुनाव आयोग आगामी 6 अक्टूबर तक बिहार में चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग जल्द वहां का दौरा आरंभ करेगा। उसने इसके लिए वहां के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उधर सभी सियासी दलों ने भी कमरकस ली है। भारत की राजनीति में बिहार हमेशा से एक प्रयोगशाला रहा है। यहां से उठे आंदोलन कभी दिल्ली की सत्ता को हिला देते हैं तो कभी देश की नई राजनीतिक दिशा तय कर देते हैं। इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव एक नए मोड़ पर खड़ा है।

राजनीतिक दलों की पारंपरिक रणनीतियों के बीच अब सनातनी राजनीति का शंखनाद सुनाई दे रहा है। और यही कारण है कि पटना को देश की पहली सनातनी राजधानी बनाने की चर्चा जोरों पर है। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने कहा की बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और वे गौ भक्त होंगे। इस मौके पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि गौ रक्षा हमारी आस्था का विषय ही नहीं बल्कि यह हमारे समाज और संस्कृति की भी आधारशिला है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं प्रत्याशियों को वोट दें जो गौ रक्षा को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संकल्पित हों।

पटना ही क्यों बने सनातनी राजधानी

पटना को सनातनी राजधानी बनाने की बात अचानक नहीं उठी है। इसके पीछे कई कारण हैं। बिहार की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर, जिसमें नालंदा, वैशाली और बोधगया जैसी जगहें शामिल हैं। राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में बिहार का लंबा इतिहास रहा है जेपी आंदोलन से लेकर मंडल और कमंडल की राजनीति सब का जनक बिहार ही रहा है। ऐसे में हिंदू समाज के भीतर जातीय संतुलन और उसका चुनावी असर जो बार-बार सत्ता का नक्शा बदलता रहा है। क्या कुछ नया गुल खिलाएगा। इस पृष्ठभूमि में शंकराचार्य का दावा कि पटना सनातनी राजधानी बनेगा केवल धार्मिक नहीं बल्कि गहरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का संकेत है।

एसआईआर का राष्ट्रव्यापारी विरोध करेंगे : खरगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एसआईपर पर बोलते हुए कहा कि बिहार की तर्ज पर अब पूरे देश में मतदाता सूची से लाखों नाम काटने की साजिश रची जा रही है। खरगे ने कहा कि वोट चोरी का मतलब है दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के राशन, पेंशन, दवाइयां, बच्चों की छात्रवृत्तियां और परीक्षा पत्र चुराना है। ऐसे में यह तय किया गया है कि हम एसआईआर का राष्ट्रव्यापारी विरोधी करेंगें।

जनता का दृष्टिकोण

बिहार के गांव से लेकर शहर तक सभी जगहलोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि धर्म की राजनीति से पेट नहीं भरता तो कोई यह मान रहा है कि अब खुलकर सनातन की आवाज उठनी चाहिए। युवा वर्ग इसे राजनीति का नया फास्ट फूड कहकर मजाक भी उड़ा रहा है। अभी खाओ थोड़ी देर में भूल जाओ। जैसी बाते भी हो रही है। जनता की इस विविध प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि चुनावी हवा में अनिश्चितता बनी हुई है।

बीजेपी की उलझन

भाजपा के सामने सबसे बड़ी उलझन यही है कि वह शंकराचार्य के इस कदम का समर्थन करे या विरोध। समर्थन करने पर यह संदेश जाएगा कि भाजपा अब राजनीतिक हिंदुत्व से आगे बढ़कर धार्मिक हिंदुत्व की राजनीति को पूरी तरह स्वीकार कर रही है। विरोध करने पर पार्टी अपने कोर वोट बैंक को नाराज कर सकती है। भाजपा के लिए बिहार विधानसभा चुनाव नित्य नये अनुभव सामने ला रहा है। अभी चिराग पासवान की चुनौती का समान्य हल नही निकल पाया है ऐसे में गौ भक्तों का चुनाव लड़ने का एलान एक नई हलचल पैदा कर रहा है।

पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा

कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गये। कार्यसमिति ने कहा कि भाजपा/आरएसएस का संविधान पर लगातार हमला जारी है और लोकतंत्र की बुनियादी धारणाओं को ईट दर ईट कमजोर किया जा रहा है। प्रस्ताव में कहा गया कि भाजपा राज में सामाजिक न्याय रौंदा जा रहा है। आरक्षण को लगातार खत्म किया जा रहा है और निजीकरण की आड़ में वंचित वर्गों के हक छीने जा रहे हैं।

मजबूरी में उतारने पड़ रहे हैं प्रत्याशी

शंकराचार्य ने बताया कि हम सभी राष्ट्रीय पार्टी के दिल्ली कार्यालय पर गए और पूछा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अपना पक्ष लोकसभा सदन में रखिए और अपने पक्ष को हमें बताइए लेकिन अभी किसी भी राजनीतिक दल ने अपना पक्ष गौ माता के विषय में नहीं बताया इसलिए अब मजबूरी में हमें बिहार विधानसभा चुनाव में गौ भक्ति प्रत्याशी उतारना पड़ रहे हैं। शंकराचार्य ने यह भी घोषणा की है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद औपचारिक रूप से यह बताया जाएगा कि कौन-कौन से उम्मीदवार उनकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं।

एआईएमआईएम अध्यक्ष ने अभियान की शुरुआत अकेले ही की

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के सीमांचल क्षेत्र में अपने अभियान की शुरुआत अकेले ही कर दी है। उनकी पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) के साथ गठबंधन को लेकर अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। 2020 के चुनावों में एआईएमआईएम ने 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और पांच पर जीत हासिल की, ये सभी सीमांचल क्षेत्र में हैं जहां मुस्लिम आबादी अच्छी-खासी

है। इस क्षेत्र में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिले शामिल हैं। लोकसभा चुनावों में एआईएमआईएमने बिहार में 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी की बिहार इकाई के प्रमुख अख्तरुल ईमान ने बिहार में संभावित चुनाव पूर्व गठबंधन के संबंध में तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है। किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा कि अख्तरुल ईमान ने यादव से कहा कि एआईएमआईएम नवंबर में होने वाले चुनाव में 243 में से छह सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस गठबंधन में फिलहाल राजद प्रमुख साझेदार है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है तथा कई अन्य पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि अख्तरुल ईमान ने यहां के नेता प्रतिपक्ष (तेजस्वी यादव) को पत्र लिखा है, और हमने मीडिया के माध्यम से कहा है कि एआईएमआईएम गठबंधन के लिए तैयार है। अख्तरुल ईमान ने यह भी लिखा है कि वे हमें छह सीटें दे सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि हम आरजेडी से गठबंधन करने के लिए तैयार थे। आरजेडी को इस बार फिर सीमांचल में हराएंगे।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

वकील आमजन की आवाज उनका भी संरक्षण हो

> **अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रारूप में अधिवक्ताओं पर हिंसा, धमकी, उत्पीड़न, संपत्ति का नुकसान और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है। दोषी पाए जाने पर छह महीने से पांच वर्ष तक की सजा और पचास हजार से दस लाख रुपये तक का जुर्माना होगा, जबकि पुनरावृत्ति की स्थिति में यह सजा दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।**

न्याय दिलाने के लिए आमजन की आवाज अदालतों में उठाने वाले वकीलों पर पिछले कुछ दिनों से हमले बढ़ गए हैं। यह लोकतंत्र में आम जनता के संरक्षक की भूमिका में होते हैं। एक तरह से न्याय की रीढ़ होते है। इन पर वार चिंता विषय है। अब इनके लिए भी अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने की चर्चा होने लगी है। सरकारों को इस पर गंभीर होना होगा। ये न्यायिक प्रणाली पर करारी चोट है। बता दे 17 सितंबर की वाराणसी घटना के बाद 20 सितंबर 2025 को विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अब भी ठोस कदम नहीं उठाती तो अधिवक्ता समाज का धैर्य टूट जाएगा। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग उत्तर प्रदेश में लगातार तेज हो रही है। हापुड़ से वाराणसी तक हुई घटनाओं ने वकीलों की असुरक्षा को उजागर किया है। विधि आयोग और बार काउंसिल अपनी सिफारिशें सरकार को दे चुके हैं। अब जरूरत है कि विधानमंडल तुरंत अधिनियम लागू कर न्यायपालिका की रीढ़ को मजबूती दे।

लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में वकील समाज का अभिन्न हिस्सा है। अदालत की चौखट पर जब आम नागरिक न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचता है, तो उसका सबसे बड़ा सहारा अधिवक्ता ही होता है। अधिवक्ता न केवल अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हैं, बल्कि न्यायपालिका और जनसाधारण के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करते हैं। किंतु दुखद है कि जो वर्ग कानून और व्यवस्था की रक्षा करता है, वही आज खुद असुरक्षित है। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की शुरुआत जुलाई 2021 में हुई, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका मसौदा प्रस्तुत किया। इसमें अधिवक्ताओं को हिंसा, धमकी और उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा के ठोस प्रावधान रखे गए। 2022 में संसद की स्थायी समिति ने मसौदे की समीक्षा कर संशोधनों की सिफारिश की। इसके बाद मार्च 2023 में राजस्थान पहला राज्य बना जिसने यह अधिनियम पारित कर अधिवक्ताओं को सुरक्षा का कवच दिया और अन्य राज्यों में भी उम्मीद जगाई। उत्तर प्रदेश में यह मांग 29 अगस्त 2023 की हापुड़ घटना के बाद और तीव्र हो गई। उस दिन पुलिस ने न्यायालय परिसर में निहत्थे अधिवक्ताओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। न्याय की रक्षा करने वाले स्वयं न्यायालय परिसर में ही अपमानित और घायल किए गए। यह दृश्य पूरे प्रदेश की बार एसोसिएशनों को झकझोर गया और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग को और प्रबल बना दिया। इसके विरोध में 4 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने तीन-दिवसीय हड़ताल की घोषणा की और अदालतों में कामकाज ठप हो गया।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

ट्रंप की एच-1बी आपदा को अवसर में बदले भारत

शिव कांत शर्मा

अमेरिका की एच1-बी वीजा व्यवस्था से राष्ट्रपति ट्रंप की चिढ़ नई नहीं है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी पद संभालते ही अप्रैल, 1917 में एच-1बी वीजा की शर्तें कड़ी करने और संख्या घटाने का फरमान जारी कर दिया था। फिर भी, यह शायद ही किसी ने सोचा हो कि एच-1बी वीजा पर एक लाख डॉलर या लगभग 88 लाख रुपये की फीस थोप दी जाएगी। इसलिए फरमान जारी होते ही एच-1बी वीजा धारकों और उनकी कंपनियों में ऐसी अफरा-तफरी मची कि अमेरिका से बाहर छुट्टी पर गए कुछ वीजा धारक हजारों डॉलर के वापसी के हवाई टिकट खरीद बैठे ताकि फरमान लागू होने से पहले अमेरिका लौट जाएं। ट्रंप की प्रेस सचिव कैरलाइन लेविट और प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन के स्पष्टीकरणों के बाद लोग थोड़ा आश्वस्त हुए। स्पष्टीकरण में बताया गया कि एक लाख डॉलर की फीस एच-1बी वीजा पर आने वाले पेशेवर की जगह उसे लाने वाली कंपनी को भरनी होगी और वह हर वर्ष की जगह केवल एक बार भरनी होगी। वीजा की समय सीमा बढ़वाने और छुट्टियां बिताकर लौटने पर कोई फीस नहीं देनी होगी। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर कुछ विशेष कंपनियों को विशेष परिस्थितियों में छूट भी मिल सकती है। इससे एमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी उन अमेरिकी कंपनियों को छूट मिलने की संभावना भी बन गई है जो सबसे बड़ी संख्या में एच-1बी वीजा प्रतिभाओं को बुला रही हैं। इससे यह संकेत भी मिलता है कि एच-1बी वीजा पर यह फीस अमेरिका की प्रतिभाओं के रोजगार बचाने की जगह व्यापार वार्ताओं में भारत की बांह मरोड़ने के लिए लगाई गई है। गनीमत इस बात की है कि हर साल जारी किए जाने वाले एच-1बी वीजाओं की संख्या नहीं घटाई गई है। लेकिन नियमों को कड़ा करते हुए वीजा आवेदन बड़ी संख्या में रद्द किए जाने की पूरी संभावना है। बहरहाल, एक लाख डॉलर की फीस और अधिक आवेदन रद्द होने का सबसे बड़ा असर भारत पर ही पड़ेगा क्योंकि हर साल जारी होने वाले 85 हजार एच-1बी वीजाओं में से 72 प्रतिशत से अधिक वीजा भारतीय पेशेवर और अमेरिकी स्नातकोत्तर डिग्रियों वाले शोध छात्र ही हासिल करते हैं। इनमें से भी 65 हजार वीजा तो एमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट मेटा, गूगल, टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बुलाई जाने वाली प्रतिभाओं के लिए हैं जो चाहें तो एक लाख डॉलर की फीस भर सकती

हैं या फिर अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने की जगह भारत में रखकर वही काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करा सकती हैं। गंभीर समस्या उनकी है जो अमेरिकी यूनिवर्सिटियों से स्नातकोत्तर डिग्रियां हासिल करने के बाद अमेरिका में रहकर किसी अमेरिकी कंपनी या संस्था में काम करना, अपना कारोबार खोलना या शोध और विकास का काम करना चाहते हैं। बीस हजार एच-1बी वीजा इन्हीं प्रतिभाओं के लिए आरक्षित रहते हैं। इनके और इनकी कंपनियों व संस्थाओं के लिए एक लाख डॉलर फीस जुटा पाना बहुत कठिन होगा। भारत समेत दुनियाभर से श्रेष्ठतम प्रतिभाएं पढ़ने-पढ़ाने और शोध करने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में आती हैं। वे यहां नई-नई खोज करती हैं, उनका कारोबारों और जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रयोग करती हैं जिससे अमेरिका के विकास को गति मिलती है। पूर्व राष्ट्रपति रेगन के शब्दों में, अमेरिका में आपकी पृष्ठभूमि को नहीं, सपनों को महत्व दिया जाता है। यही अमेरिका का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है। ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि वे हर काम का दाम वसूल करने के फेर में दुनिया भर से अमेरिका आने वाली प्रतिभाओं के सपनों को तो तोड़ ही रहे हैं, अमेरिका की उच्च तकनीक और नवाचार शक्ति के उस स्रोत को भी सुखा रहे हैं जिसने अमेरिका को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महाशक्ति बनाया है। प्रतिभाएं तैयार करने में बड़ी मात्रा में देशों के संसाधन, श्रम और समय लगता है। उन्हें प्रोत्साहित करने और उनका सदुपयोग करने की जगह उन्हें रोकने के लिए भारी-भरकम फीस थोपने की नीति समझ से परे है। वैसे यही सवाल भारत से भी किया जा सकता है। अपनी जिन प्रतिभाओं के लिए अमेरिका जैसे विकसित देशों के दरवाजे बंद होने पर भारत में जितनी भावनाएं आहत होती हैं उतनी अपनी प्रतिभाओं के पलायन से क्यों नहीं होतीं? आखिर हमारी प्रतिभाएं अपने सारे संसाधन, श्रम और बुद्धि अपने समाज और देश को छोड़कर भागने में क्यों लगा रही हैं? क्या यह अपने समाज की कुव्यवस्था के प्रति बढ़ते सामूहिक अविश्वास का प्रदर्शन नहीं है? ट्रंप ने वीजा की यह फीस चाहे जिस वजह से थोपी हो पर क्या यह भारत को सोचने और आपदा में अवसर तलाश करने को विवश नहीं करती? भारत ने हमेशा संकट से विवश होकर ही सुधार किए हैं। साठ के दशक में अन्न की कमी और भुखमरी से विवश होकर हरित क्रांति की। 1991 में देश दिवालिया हो जाने पर आर्थिक सुधारों की तरफ़ कदम बढ़ाए।

ग्रामीण सरोकारों के अग्रदूत रहे चौ. देवीलाल

के.सी. त्यागी

नौ अगस्त, 1974 को चौ.चरण सिंह के नेतृत्व में लोकदल का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्र में सत्तारूढ़ इंदिरा सरकार के विरुद्ध एक मजबूत विकल्प तैयार करना था। वर्ष 1971 के चुनाव में सभी विपक्षी दल धराशायी हो चुके थे। चौ. चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमये, राज नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, बलराज मधोक आदि नेता पराजित हो गए थे। इंदिरा सरकार मनमाने तरीके से फैसले लेकर अधिनायकवादी हो रही थी। देश के लगभग सभी राज्यों में कांग्रेसी सरकारें थीं। पंजाब के बंटवारे के बाद उन दिनों चौ. बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और इंदिरा परिवार के करीबी लोगों में उनकी गिनती होती थी। गुड़गांव में 250 एकड़ जमीन संजय गांधी मारुति कंपनी को अलॉट कर काफी ख्याति प्राप्त कर चुके थे। एक अक्खड़ और दबंग राजनेता की छवि वे बना चुके थे। लोकदल में शामिल नेताओं की लंबी फेहरिस्त बन गई।

उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके बीजू पटनायक, स्वतंत्र पार्टी के नेता एवं सांसद पीलू मोदी, जयपुर की महारानी गायत्री देवी, राजस्थान के किसान नेता चौ. कुंभाराम आर्य और चौ. दौलत राम सारण, समाजवादी आंदोलन के शीर्षस्थ नेता राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर, मामा बालेश्वर दयाल, रवि राय, रामसेवक यादव, मुलायम सिंह यादव आदि नेता अपने समर्थकों के साथ नए विकल्प को मजबूत करने में जुटने लगे। उस समय जनसंघ (अब भाजपा) संगठन के तौर पर अपनी उपस्थिति जोरदार तरीके से दर्ज नहीं कर पा रहा था। अटल जी अवश्य राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रखर वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। जनसंघ के कई नामी गिरामी नेता भी लोकदल में शामिल हो चुके थे। जिसमें पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक, पीतांबर दास और एम.एल. सोंधी आदि थे। हरियाणा और पंजाब में किसान मजदूरों के कई आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। स. प्रकाश सिंह बादल और चौ. देवीलाल किसानों के सवालों पर रोज पंचायत आयोजित कर सरकार की परेशानियां बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर चौ. चांदराम हरियाणा के दलितों को एकताबद्ध कर राज्य और केंद्र सरकार की नयी घेराबंदी में लगे थे।

चौ. देवीलाल और चौ. चांदराम दोनों के लोकदल में शामिल होने से हरियाणा की राजनीति में मानो भूचाल आ गया था। बंसीलाल के आतंक का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं था। कांग्रेस पार्टी की राजनीति में चौ. देवीलाल, चौ. बंसीलाल के सीनियर नेता थे। चौ. देवीलाल का परिवार आजादी के संग्राम में अग्रणी था। यद्यपि उस समय सर छोटू राम का समूचे पंजाब के किसानों पर बेहद असर था। जमींदारा पार्टी किसान हितों की एकमात्र पार्टी मानी जाती थी। हिसार में चौ. देवीलाल और रोहतक में चौ. रणबीर सिंह (भूपेंद्र हुड्डा के पिता) ही कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए थे। यूं भी कांग्रेस पार्टी का समूचा नेतृत्व उस समय गैर-किसान नेताओं के हाथों में था। वर्ष 1956 में चौ. देवीलाल संयुक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे और इससे पूर्व 1952 में सर छोटू राम की जमींदारा पार्टी के उम्मीदवार को हराकर विधानसभा में चुने गए।

चौ. देवीलाल ने एक रोचक प्रसंग का जिक्र किया है कि वे जेल से रिहा होकर हिसार रेलवे स्टेशन के गेस्ट रूम में पहुंचे तो वहां सर छोटू राम से उनकी मुलाकात हो गई। छोटू राम लाहौर जाने की तैयारी में थे। उन्होंने चौ. देवीलाल को बुलाकर समझाने का प्रयास किया कि कांग्रेस अभिजात्य वर्ग की पार्टी है। समूचा नेतृत्व इसी वर्ग का है। हमें सिर्फ कार्यकर्ता और वोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बेवजह अपना वक्त और भविष्य इस पार्टी में बर्बाद मत करो। चौ. देवीलाल उस समय आजादी के आंदोलन के बड़े नेता के रूप में ख्यात हो चुके थे। लेकिन आजादी के बाद भी लंबे समय तक संयुक्त पंजाब की कमान कभी किसान परिवार के नेताओं के हाथ में नहीं लगी। सर छोटू राम की दूरदर्शिता इससे साबित हुई। हरियाणा क्षेत्र के साथ हो रहे भेदभाव को उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उठाना शुरू किया, जिसकी परिणति 1966 में पृथक राज्य हरियाणा के अस्तित्व में आने के रूप में हुई। समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया उस समय गैर कांग्रेसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। डॉ. लोहिया उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कन्नौज से समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव मैदान में थे।

चौ. देवीलाल गाड़ियों के काफिले के साथ वहां पहुंचे और सघन चुनाव प्रचार में लग गए। डॉ. लोहिया विजयी रहे। चौधरी देवीलाल ने उन्हें बधाई देते हुए सारे देश में इस मिशन को लेकर भ्रमण करने का आग्रह किया और कहा कि इसमें वे भी उनके सक्रिय साथी की भूमिका में होंगे। इतिहास गवाह है कि 1967 में हरियाणा प्रांत में बनी पहली गैर-कांग्रेसी सरकार, जिसका नेतृत्व राव वीरेन्द्र सिंह ने किया, उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था। वर्ष 1974 के गुजरात के छात्र आंदोलन से समूचे देश में कांग्रेस विरोधी वातावरण बनने लगा और बिहार में जेपी के सक्रिय होने पर इसका राष्ट्रव्यापी स्वरूप उभरा। हरियाणा में उस समय अघोषित आपातकाल जैसा था लेकिन चौ. देवीलाल ने उस चुनौती को स्वीकार कर कुरुक्षेत्र में जेपी की सभा की घोषणा कर दी। जेपी को करनाल में युवक कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन जन आक्रोश के चलते कुरुक्षेत्र में चौ. देवीलाल के प्रयासों से बड़ी सभा आयोजित हुई। इसी बीच रोरी उपचुनाव में जनता ने चौ. देवीलाल को बहुमत से जिता कर भेजा।

विश्व पर्यटन दिवस

हर देश में पर्यटन के महत्व की दिलाता है याद

जैसे-जैसे हम विश्व पर्यटन दिवस 2025 के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे-वैसे इसके प्रति उत्सुकता बढ़ रही है। इस अवसर को मनाने और सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें उद्योग के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने वाले सम्मेलन, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के उद्देश्य से कार्यशालाएं और स्थानीय परंपराओं की समृद्धि को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रदर्शनियां शामिल हैं। प्रतिभागी वैश्विक एकता और समझ को बढ़ावा देने में पर्यटन के महत्व के बारे में जान सकते हैं। इस बार विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जायेगा। यह दिन दुनिया को दुनिया और हर देश में पर्यटन के महत्व की याद दिलाता है। दुनिया भर के लोगों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि पर्यटन ने उन्हें कैसे बदला है, चाहे वह नई संस्कृतियों की खोज के माध्यम से हो या अनोखे रोमांच का अनुभव करके।

2025 के लिए मेजबान देश

2025 में जॉर्जिया विश्व पर्यटन दिवस के लिए एक आदर्श मेज़बान के रूप में उभर रहा है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के संगम पर बसा जॉर्जिया अपने समृद्ध इतिहास, मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों और संस्कृतियों के अनूठे मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। देश ने अपने पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो सालाना लाखों अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है। जॉर्जिया अपने प्राचीन चर्चों, प्रसिद्ध वाइन क्षेत्रों और मनमोहक पर्वत श्रृंखलाओं के साथ इस बात का उदाहरण है कि कैसे पर्यटन सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ा सकता है और शांति को बढ़ावा दे सकता है।

इतिहास

ऐतिहासिक रूप से विश्व पर्यटन दिवस पहली बार 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के क़ानूनों को अपनाने के उपलक्ष्य में 1980 में मनाया गया था। दशकों से, यह दिवस एक वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है, जहां दुनिया भर के देश पर्यटन के लाभों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सम्मेलनों और कार्यशालाओं से लेकर सांस्कृतिक प्रदर्शनियों तक, इन आयोजनों का उद्देश्य व्यक्तियों और संगठनों को स्थायी प्रथाओं में संलग्न होने के लिए शिक्षित और प्रेरित करना है।

2025 की थीम

हर साल, विश्व पर्यटन दिवस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुनी गई एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। 2025 का विषय पर्यटन और हरित निवेश है। यह थीम स्थायी पर्यटन अवसंरचना और परियोजनाओं में निवेश की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देती है जो समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं को समृद्ध बनाने के साथ-साथ हमारे ग्रह की रक्षा में भी मदद करें। हरित निवेश पर्यटन व्यवसायों और यात्रियों दोनों को ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करें, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दें और सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करें।

हंसना मना है

भक्त- भगवान मैं पापी हूं! मुझे दर्द दो, दुख दो, मुझे बर्बाद कर दो, परेशानी दो, मेरे पीछे भूत लगा दो! भगवान- अबे एक लाइन में बोल ना कि बीबी चाहिए!

गर्लफ्रेंड- मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है। बॉयफ्रेंड- कर दी न छोटी बात, पगली यह ले 10 रुपये। अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स ले आ। गर्लफ्रेंड बेहोश।

पत्नी- इतने साल हो गये शादी को आज तक कुछ नहीं दिया, पति- दिल तो दिया है और क्या चाहिए, पत्नी- नहीं जानू, कोई सोने की चीज दिलाओ ना, पति- चलो शाम को नया तकिया ला दूंगा, खूब मजे से सोना।

ज्योतिषी- अच्छा, तो आप अपने प्रेमी का भविष्य जानना चाहती हैं? गीता- जी नहीं, उसका भविष्य तो मेरे हाथ में है। आप तो उसके अतीत के बारे में बताइये?

रंग से गोरी न थी लेकिन सुन्दर थी..बहुत ऊंची न थी, लेकिन मेरे लिए योग्य थी, मेरे कदमो से कदम मिलाती थी, मंदिर-मस्जिद आने से इनकार करती थी, लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कही भी जाओ मेरे लिए रुक जाती थी, वो जैसी भी थी मेरी चप्पल थी.. पता नहीं कौन उठाकर ले गया?

कहानी | आधा इनाम

यह बात तब की है जब शहंशाह अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात हुई थी। उस समय सभी बीरबल को महेश दास के नाम से जानते थे। एक दिन शहंशाह अकबर बाजार में महेश दास की होशियार से खुश होकर उसे अपने दरबार में इनाम देने के लिए बुलाते हैं और निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी देते हैं। कुछ समय के बाद महेश दास सुल्तान अकबर से मिलने का विचार बनाकर उनके महल की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर महेश दास देखते हैं कि महल के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और दरबान हर व्यक्ति से कुछ न कुछ लेकर ही उन्हें अंदर जाने दे रहा है। जब महेश दास का नंबर आया, तो उसने कहा कि महाराज ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है और उसने सुल्तान की अंगूठी दिखाई। दरबान के मन में लालच आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर अंदर जाने दूंगा अगर तुम मुझे इनाम में से आधा हिस्सा दो तो। दरबान की बात सुनकर महेश दास ने कुछ सोचा और उसकी बात मानकर महल में चले गए। दरबार में पहुंचकर वह अपना नंबर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही महेश दास की बारी आई और वो सामने आए, तो शहंशाह अकबर उन्हें देखते ही पहचान गए और दरबारियों के सामने उनकी बहुत तारीफ की। बादशाह अकबर ने कहा कि बोलो महेश दास इनाम में क्या चाहिए। तक महेश दास ने कहा कि महाराज मैं जो कुछ भी मांगूगा क्या आप मुझे इनाम में देंगे? बादशाह अकबर ने कहा कि बिल्कुल, मांगों क्या मांगते हो। तब महेश दास ने कहा कि महाराज मुझे पीठ पर 100 कोड़े मारने का इनाम दें। महेश दास की बात सुनकर सभी को हैरानी हुई और बादशाह अकबर ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तब महेश दास ने दरबान के साथ हुई पूरी घटना बताई और अंत में कहा कि मैंने वादा किया है कि इनाम का आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा। तब अकबर ने गुस्से में आकर दरबान को 100 कोड़े लगवाए और महेश दास की होशियारी देखकर अपने दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में रख लिया। इसके बाद अकबर ने उनका नाम बदलकर महेश दास से बीरबल कर दिया।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष
प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी। धनार्जन होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। प्रमाद न करें। भाइयों की मदद मिलेगी।

वृषभ
संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। बेरोजगारी दूर होगी। धन की आवक बनी रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य न करें। लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी।

मिथुन
रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। पूंजी निवेश बढ़ेगा। प्रचार-प्रसार से दूर रहें।

कर्क
क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दु:खद समाचार मिल सकता है। चिंता बनी रहेगी। व्यापार-व्यवसाय में सावधानी रखें। वास्तविकता को महत्व दें।

सिंह
मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु शांत रहेंगे। धनार्जन होगा। आज विशेष लाभ होने की संभावना है। सगे-संबंधी मिलेंगे।

कन्या
मेहमानों का आवागमन होगा। उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। मान बढ़ेगा। जल्दबाजी न करें। जोखिम के कार्यों से दूर रहें। पराक्रम में वृद्धि होगी।

तुला
यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल लाभ देंगे। भेंट आदि की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता रहेगी। व्यापार में उन्नति के योग हैं।

वृश्चिक
वाणी पर नियंत्रण रखें। अप्रत्याशित बड़े खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है, जोखिम न लें। अजनबी व्यक्ति पर विश्वास न करें।

धनु
नई योजना बनेगी। नए अनुबंध होंगे। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है। परिवार की समस्याओं की चिंता रहेगी।

मकर
नए अनुबंधों का लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। पूछ-परख रहेगी। रुके कार्य बनेंगे। जोखिम न लें। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। खानपान पर नियंत्रण रखें।

कुम्भ
कोर्ट व कचहरी के काम निबटेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। तंत्र-मंत्र में रुचि रहेगी। धनार्जन होगा। प्रमाद न करें। संतान के कार्यों से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मीन
वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। दूसरों की जमानत न लें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है।

करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 में अब नजर आयेंगे विक्रांत मेसी

विक्रांत मैसी इन दिनों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने को लेकर चर्चाओं में हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उन्हें फिल्म '12वीं फेल' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अब अभिनेता ने अपनी आगामी फिल्म को लेकर बात की है। इसमें उन्होंने बताया कि वो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की एक मच अवेटेड फिल्म में नजर आने वाले हैं। जानिए कौन सी है वो फिल्म, जिसमें विक्रांत निभाएंगे प्रमुख भूमिका?

विक्रांत मैसी अब तक एक कॉमन मैन के ही किरदार में दिखाई दिए हैं। लेकिन अब वो करण जौहर की आगामी फिल्म में महंगे कपड़ों और स्टाइलिश सनग्लासेज में नजर आएंगे। टाइम्स नाउ के साथ बातचीत के दौरान विक्रांत मैसी ने बताया कि अब लोग उन्हें जल्द ही डिजाइनर कपड़े और फैंसी सनग्लासेस में देख पाएंगे। इस दौरान अभिनेता ने खुलासा किया कि वो धर्मा प्रोडक्शंस की 'दोस्ताना 2' में नजर आने वाले हैं। एक्टर ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह खबर पहले ही आ चुकी है। मुझे नहीं पता कि मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं दोस्ताना 2 कर रहा हूं। मैं अपनी पहली धर्मा प्रोडक्शन फिल्म कर रहा हूं। आप मुझे अच्छे डिजाइनर कपड़े पहने हुए देखेंगे। करण जौहर यह सुनिश्चित करेंगे कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और मैं फैंसी सनग्लासेस पहनूं। यूरोप में कहीं शूटिंग कर रहा हूं।'

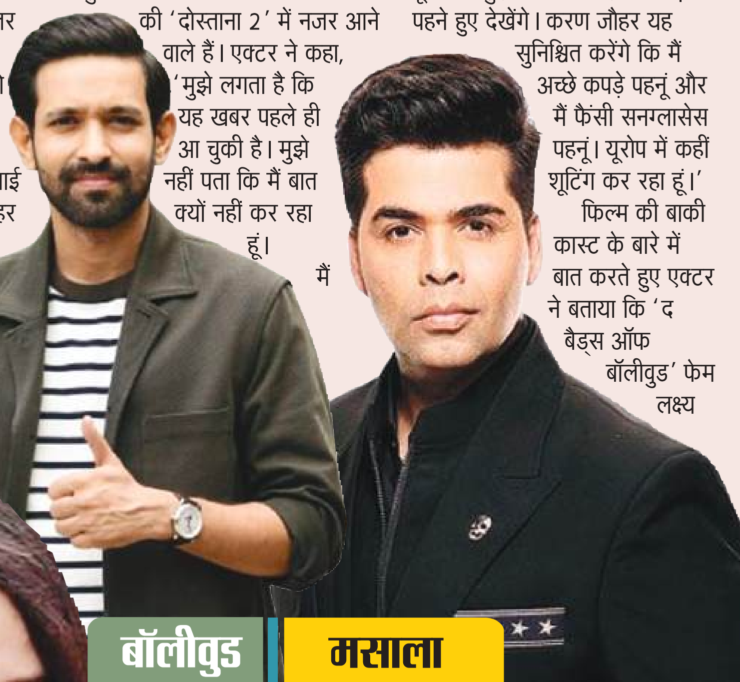

फिल्म की बाकी कास्ट के बारे में बात करते हुए एक्टर ने बताया कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फेम लक्ष्य लालवानी भी 'दोस्ताना 2' का हिस्सा हैं। हालांकि, विक्रांत ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस के बारे में कोई भी जानकारी देने से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा, 'अब हीरोइन को तो सरप्राइज ही रहने दो। मुझे लगता है कि उनके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। वो करण सर ही बोलेंगे तो बेहतर है। उसकी भी तो बड़ी घोषणा है।' 'दोस्ताना 2' की जब घोषणा हुई थी तब फिल्म में कार्तिक आर्यन, जान्हवी कपूर और लक्ष्य लालवानी प्रमुख भूमिका में नजर आने थे। लेकिन बाद में कुछ क्रिएटिव मतभेदों के कारण कार्तिक आर्यन फिल्म का हिस्सा नहीं रहे। इसके बाद फिल्म अटक गई थी। अब विक्रांत मैसी और लक्ष्य फिल्म में लीड रोल निभाएंगे। लेकिन फिल्म की हीरोइन कौन होगी, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

विक्रांत मैसी के वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेता आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की बायोपिक में व्यस्त हैं।

बॉलीवुड | मसाला

मुझे अबतक 30-40 शादी के प्रस्ताव आ चुके हैं : अनाया

इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल काफी चर्चाओं में बना हुआ है। शो में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे खुलासे होते हैं, जो दर्शकों को हैरान कर देते हैं। गुरुवार के दिन शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें अनाया बांगड़ अपनी पर्सनल लाइफ में हुई अजीब घटनाओं का खुलासा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हजारों लोगों ने शादी का प्रस्ताव भेजा और कुछ ने तो इसे स्वीकार ना करने पर अनाया को धमकियां भी दीं।

राइज एंड फॉल शो का नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें आकृति नेगी और अनाया बांगर बात करती दिख रही हैं। वीडियो की शुरुआत में आकृति, अनाया से पूछती हैं, 'वो कंटेट बनाती हैं?' इसके जवाब में अनाया ने कहा, 'हां, मैं वहां बिल्कुल सच बोलती हूं।' फिर आकृति ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया मिलती है? इसके जवाब में अनाया ने कहा कि जितना नापसंद लोग उन्हें कमेंट सेक्शन में करते हैं, उतना ही प्यार उन्हें लोग डीएम में भेजते हैं।

आगे अनाया ने बताया, 'मुझे अबतक 30-40 शादी के प्रस्ताव आ चुके हैं। बिना कुछ जाने बिना कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, नहीं तो अपने आप को जान से मार डालूंगा।' इतना सुनकर आकृति हैरान हो जाती हैं, फिर दोनों हंसने लगते हैं।

बॉलीवुड | मन की बात

मैं पहले के गाने अपने बच्चों को नहीं दिखा सकती : सपना चौधरी

सपना चौधरी का नाम अब सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। सपना ने अपने इस सफर से बहुत कुछ सीखा है। सपना पर अश्लील गाने करने का आरोप लग चुका है, हालांकि पहले वो नहीं समझ पाती थीं कि उसमें अश्लील क्या है, लेकिन अब वो खुद मानती हैं कि अपने किए पहले के गाने वो अपने बच्चों को नहीं दिखा सकतीं। सपना ने माना कि उन्हें अपने अतीत से परेशानी होती है। वो पहले के किए गाने अपने बच्चों को नहीं दिखा सकतीं क्योंकि इससे उनपर गलत असर पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने अपने अंदर कई सुधार किए और अपनी एक लिमिट तय की। सपना बोलीं- मेरे बच्चे मेरे गाने आज देखते हैं, लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं तो मैं मेरे बच्चों को वो गाने नहीं दिखाऊंगी। क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि मैं बहुत एनर्जी के साथ परफॉर्म करती हूं। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि कुछ चीजों की लिमिट्स होनी चाहिए। अभी तो मैं जो भी करती हूं लिमिट में करती हूं। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो, जैसे मैंने कोई भी स्टेप किया, अगर उस स्टेप को मैं ओवर कर दूं तो वो स्क्रीन पर गंदा आएगा। लेकिन उसी स्टेप को अगर मैं आज लिमिट में करूं तो बहुत प्यारा दिखता है। ये मैंने वक्त के साथ सीखा है। अब मैं भी इंसान हूं गलतियां करूंगी तो ही सीखूंगी। अगर गलतियां नहीं करूंगी तो सीखूंगी कैसे? मैंने भी साल-दर-साल खुद पर काम किया है। मैं ऐसे ही नहीं यहां पहुंची हूं। कुछ तो किया ही होगा ना। सपना ने आगे बताया कि कैसे वक्त के उन्होंने ध्यान दिया कि उनका शो देखने सिर्फ मर्द ही आते हैं। वो बोलीं- मुझे पता लगा कि नहीं सपना इतनी लिमिट होनी चाहिए। अगर मेरा शो देखने सिर्फ आदमी-आदमी ही आ रहे हैं, तो क्यों, यहां औरतें-बच्चे क्यों नहीं हैं। अब मैं ये समझ गई हूं तो मेरे शो में आदमियों के साथ औरतें आती हैं, बच्चे बैठे होते हैं। तब तो औरतों को आना अलाउड भी नहीं था। हमने शोज को ऐसे अपग्रेड किया, उसे लिमिट में सेट किया ताकि सब देख सके। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे बच्चे भी आज मेरे गाने देखते हैं।

एमपी को कहते हैं नदियों का मायका बेहद रोचक है इसकी खास वजह

मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि यहां से निकलने वाली नदियां पूरे भारत की प्यास बुझाती हैं। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, माही और बेतवा जैसी नदियां न सिर्फ जल देती हैं बल्कि आस्था और संस्कृति को भी संजोए हुए हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश देश के लिए जीवन दायिनी माना जाता है। आइए जानते है प्रमुख नदियों के बारे में। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। कुल 1312 किलोमीटर लंबी इस नदी में से 1077 किलोमीटर का हिस्सा सिर्फ मध्य प्रदेश में बहता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के करोड़ों लोगों को जल उपलब्ध कराती है और अंत में खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले के महू स्थित जानापाव पहाड़ियों से होता है। 1024 किलोमीटर लंबी यह नदी इटावा के पास जाकर यमुना में मिलती है। मध्य प्रदेश में इसका सफर 325 किलोमीटर लंबा है। प्राचीन ग्रंथों में इसे चर्मणवती कहा गया है और महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है। आज भी यह नदी प्रदेश की खेती और पेयजल का बड़ा आधार है। सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है, जिसमें से 509 किलोमीटर का सफर मध्य प्रदेश में है। यह नदी बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख 'सुभागधी' नाम से मिलता है। सोन नदी पर बना बाणसागर बांध प्रदेश की सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बेहद अहम है। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुलताई कस्बे से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जिसमें से 279 किलोमीटर का सफर मध्य प्रदेश में तय होता है। यह नदी सूरत के पास खंभात की खाड़ी में मिलती है। ताप्ती को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच प्राकृतिक सीमा भी माना जाता है और यह गुजरात तक जाकर करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। माही नदी का उद्गम धार जिले के मिन्डा गांव से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 576 किलोमीटर है। यह नदी धार, झाबुआ और रतलाम जिलों से बहते हुए राजस्थान और गुजरात में पहुंचती है और अंत में खंभात की खाड़ी में गिरती है। खास बात यह है कि माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, जो दो बार कर्क रेखा को पार करती है, जो इसे विशिष्ट बनाती है।

अजब-गजब | इस देश में सरेराह होता है लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार

यहां नर्क है महिलाओं की जिंदगी! लड़की जात होना पाप

पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों की जिंदगी नर्क जैसी हो चुकी है। यहां लड़की होना ही पाप माना जाता है। मासूमों का शोषण रोजाना का सिलसिला बन गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वीडियो में एक मर्द, जो औरत के भेष में नजर आया- साड़ी पहने, मेकअप करके- दो छोटी-छोटी बच्चियों के साथ सड़क पर भीख मांगता दिखाई दिया। लेकिन ये कोई साधारण दृश्य नहीं था। इस बीच वो चुपके से बच्चियों को पीट-पीटकर रुलाता नजर आया, ताकि उनके आंसू देखकर राहगीर दया खाकर पैसे दे दें।

ये वीडियो पेशावर की एक व्यस्त सड़क पर रिकॉर्ड किया गया। एक राहगीर ने इसे देखा। जब उससे सहन ना हो सका तो फोन निकालकर शूट कर लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 'औरत' का लुक बनाए मर्द बच्चियों को अपने साथ लेकर सड़क पर घूम रहा था। वो बच्चियों को ढाल बनाकर पैसे ठग रहा था। लेकिन जो चीज अन्य लोगों को नजर नहीं आई, वो ये थी कि ये शख्स चुपके से इन बच्चियों को मारकर रुला रहा था। वो कभी एक को चीटी काटता तो कभी दूसरी को नोच रहा था। इससे बच्चियां दर्द से तड़प कर रो पड़ती।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जहां इसने लाखों व्यूज बटोर लिए। लोग गुस्से से लाल हो गए और कईयों ने लिखा, ये क्रूरता बंद होनी चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान में चाइल्ड बेगिंग एक महामारी का रूप ले चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये सबसे घिनौनी शक्ल वाली चाइल्ड लेबर है, जहां बच्चे बीमारी, अपराध, शोषण और ड्रग्स की चपेट में फंस जाते हैं। 2025 में चाइल्ड एब्यूज केसेज में 20 प्रतिशत की उछाल आया है। साहिल रिपोर्ट कहती है कि हर दिन औसतन 9 बच्चे शोषण का शिकार होते हैं, जिनमें सेक्सुअल एब्यूज, अपहरण, गायब होना और चाइल्ड मैरिज शामिल है। पेशवर के खैबर पख्तूनख्वा में तो हालात और खराब हैं जहां कई बच्चे गायब हैं।

इस वीडियो में जो दिख रहा है, वो पाकिस्तानियों के लिए आम बात है। पाकिस्तान में ट्रांसवेस्टाइट या हिजड़ा कम्युनिटी को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया कि एक बेगिंग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें 47 प्रोफेशनल बेगर्स गिरफ्तार हुए—14 महिलाएं, 31 मर्द और 2 ट्रांसजेंडर। ये गिरोह बच्चे खरीदते-बेचते हैं, उन्हें पीटते हैं ताकि वे ज्यादा भीख मांगे। लाहौर में टीनएज बेगर्स पर स्टडी बताती है कि इमोशनल और फिजिकल एब्यूज आम है—सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, फिजिकल बीटिंग, साइकोलॉजिकल टॉर्चर। बच्चे गरीबी के कारण ट्रैफिकिंग का शिकार बनते हैं, जहां माफिया उन्हें कंट्रोल करता है।

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तान में लड़कियां पैदा होना पाप है। सरकार सो रही है। दूसरा बोला, ये मर्द लालच में कुछ भी कर सकता है। कई एनजीओ ने अपील की कि बच्चियों को बचाया जाए। वहीं वीडियो को लेकर लोकल पुलिस ने कहा कि जांच शुरू हो गई है। आरोपी को पकड़ने की कोशिशें जारी है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बेगिंग पर बैन लगाया था—मर्द, औरत, बच्चे या ट्रांसजेंडर सभी पर। लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया।

राष्ट्रसेवा के चिरस्थायी प्रतीक बने रहेंगे मनमोहन : खरगे

» कांग्रेस अध्यक्ष बोले - ईमानदारी और बुद्धिमता में उनके जैसा कोई नहीं

» जयंती के मौके पर याद किए गए पूर्व पीएम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जयंती के मौके पर शुक्रवार को देश के विकास में उनके योगदान को याद किया और कहा कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और राष्ट्र के प्रति नि:स्वार्थ सेवा के एक चिरस्थायी प्रतीक बने रहेंगे। सिंह का जन्म 26 सितंबर,1932 को पंजाब के गाह गांव में हुआ था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंह ने 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दीं। उनका 26 दिसंबर, 2024 को निधन हो गया था।

खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, हम राष्ट्र निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के योगदान को याद करते हैं। वह भारत के आर्थिक परिवर्तन के एक सूत्रधार थे। वह विनम्रता और बुद्धिमत्ता के धनी थे तथा सबके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करते थे और अपने कार्यों से अपनी बातों को ज्यादा प्रभावशाली बनाते थे। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के दृष्टिकोण ने अवसरों के नये द्वार खोले, एक समृद्ध मध्यम वर्ग का निर्माण किया और अनगिनत परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला। खरगे ने कहा, वह निष्पक्षता और समावेशिता में गहराई से विश्वास करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले कल्याणकारी उपायों के माध्यम से विकास और करुणा साथ-साथ चलें। उनके नेतृत्व ने हमें दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी न केवल संभव है, बल्कि शक्तिशाली भी है। खरगे ने कहा कि भारत की पीढ़ियों के लिए वह ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के एक चिरस्थायी प्रतीक बने रहेंगे तथा एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत की आकांक्षाओं वाली उनकी विरासत जीवित रहेगी।

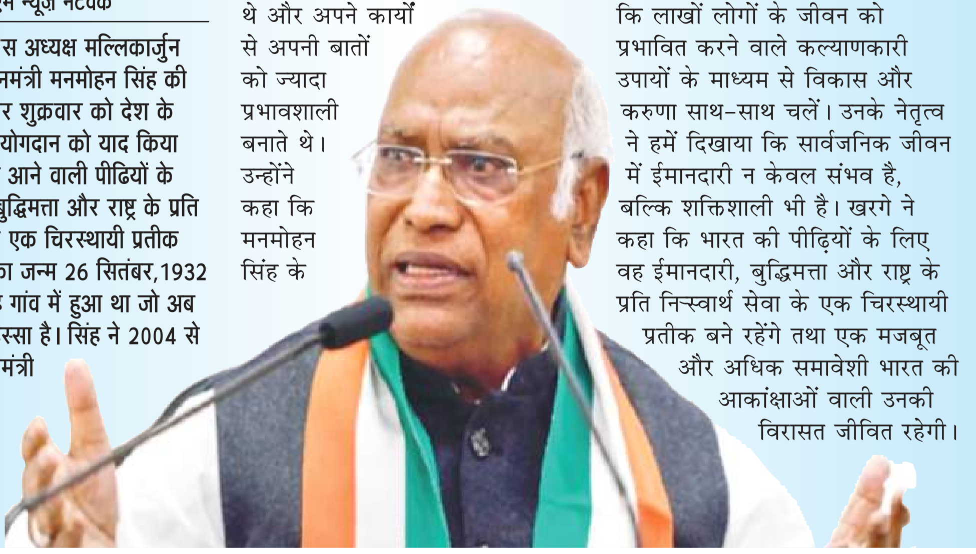

मेरी हत्या की साजिश हो रही है : पप्पू यादव

» सांसद का बड़ा आरोप- बिहार के दो बड़े नेता और अधिकारी शामिल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

सुरक्षा एजेंसियों से पप्पू यादव ने की सुरक्षा बहाल की अपील

पटना। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक महीने पहले वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन मात्र एक महीने के भीतर ही यह सुरक्षा हटा दी गई। सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि बिहार के दो बड़े नेता और दो बड़े अधिकारी मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। अगर मेरे साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसके जिम्मेदार वही दो बड़े नेता और दो बड़े अधिकारी होंगे।

पप्पू यादव ने जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस साजिश के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि संजय झा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी को बेच दिया है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक संभावनाओं का सौदा कर रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संजय झा जानते हैं कि मैं भाजपा नेता को किसी भी कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, इसलिए मेरी जान का सौदा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सीमांचल, कोसी और मिथिला में भाजपा को चुनौती देने वाला वह अकेले हैं, इसलिए उनके खिलाफ यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। पप्पू यादव ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से अपील की कि उनकी सुरक्षा बहाल की जाए. इसके अलावा सुरक्षा को लेकर इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है।

जनता झेल रही जीएसटी की मार : पटवारी

» मप्र पीसीसी चीफ ने व्यापारियों से की चर्चा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल के न्यू मार्केट में व्यापारियों से जीएसटी में हुए सुधार पर चर्चा की। इस दौरान पटवारी कई दुकानों में व्यापारियों से पूछा कि उन्हें कितना लाभ हो रहा है। पहले और अब में कितना फायदा हुआ। पटवारी ने केंद्र सरकार की जीएसटी नीति पर तीखा हमला बोला उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मल्टी स्लैब सिस्टम थोपकर व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने मांग की कि सरकार पिछले वर्षों में व्यापारियों और जनता से वसूली गई अधिक टैक्स की भरपाई करे और जीएसटी को पुनः सरल बनाया जाए।

पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने गोमांस पर जीएसटी 0 प्रतिशत कर दिया है, जिससे गो हत्या को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसको लेकर लगातार विरोध करती रहेगी। पटवारी ने मांग की कि जिस तरह आयकर रिफंड की व्यवस्था है, उसी तरह जीएसटी में भी रिफंड की नीति लागू की जाए। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी चुकाया है, उन्हें दरों में कटौती के बाद अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी 26 और 27 सितंबर को पूरे मध्य प्रदेश में इस फैसले को लेकर आंदोलन करेगी। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी सुधारों के लिए आगे भी है संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया है।

कूड़ा उठाने वाली कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन

» लखनऊ में एलएसए की कारगुजारियों से परेशान हैं आम नागरिक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। आईआईएम रोड स्थित बालाजी एंक्लेव कॉलोनी के निवासियों ने कूड़ा उठाने वाली कंपनी एलएसए के खिलाफ प्रदर्शन किया। कॉलोनीवासियों का आरोप है कि कंपनी द्वारा रिहायशी इलाके के बीच कूड़ा डंप किया जा रहा है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने दफ्ती बोर्ड लेकर नारे लगाए और कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। निवासियों ने कहा कि वे इससे पहले भी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

बालाजी सोसाइटी के अध्यक्ष अंशु अवस्थी ने बताया कि हम शांति पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। कॉलोनी में रह रहे सभी लोग गंदगी और दुर्गंध से परेशान हैं। हमारी मांग है कि कॉलोनी से कंपनी का कूड़ा डंपिंग सेटअप हटाया जाए।

पशु कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारियों का कान्हा गौशाला भ्रमण

नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नगर निगम लखनऊ ने पशु कल्याण एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारियों को कान्हा गौशाला का भ्रमण कराया। भ्रमण के दौरान अधिकारियों को पशु देखभाल, पोषण प्रबंधन, चारा भंडारण, टीकाकरण, रोग नियंत्रण और चिकित्सा सुविधाओं की आधुनिक व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि कान्हा गौशाला देश की आदर्श गौशालाओं में से एक है, जहां स्वच्छ वातावरण, संतुलित आहार और उन्नत चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि यहां अपनाई जा रही प्रणाली अन्य गौशालाओं के लिए अनुकरणीय मॉडल है। इससे न केवल पशु संरक्षण के प्रयास मजबूत होंगे बल्कि आवारा पशु समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में अपर नगर निदेशक डॉ. असलम अंसारी, डॉ. सौरभ गुप्ता, अयोध्या के अपर नगर आयुक्त भरत कुमार सहित बरेली, अयोध्या, मेरठ व अन्य नगर निगमों के अधिकारी मौजूद रहे।

वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान

» करुण को नहीं मिली जगह, जडेजा बने उपकप्तान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है। भारतीय टीम इस सीरीज में शुभमन गिल की कप्तानी में खेलने उतरेगी, जबकि रवींद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो अक्तूबर को दो मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग का जिम्मा संभालेंगे।

टीम के अनुभवी विकेटकीपर ऋषभ पंत चोट से पूरी तरह उबर नहीं सके हैं जिस कारण इस सीरीज के लिए उनका चयन नहीं किया गया है। पंत इंग्लैंड दौरे पर उपकप्तानी का जिम्मा भी संभाल रहे थे और उनकी अनुपस्थिति में अब यह जिम्मेदारी रवींद्र जडेजा को सौंपी गई है। विकेटकीपर के तौर पर जुरेल पहली पसंद हैं, जबकि बैकअप के तौर पर एन जगीदशन को भी टीम में जगह दी गई है। जसप्रीत बुमराह को वेस्टइंडीज के खिलाफ आराम नहीं दिया गया है। वहीं, उनके साथ मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। इंग्लैंड दौरे से आठ साल बाद भारतीय टीम में जगह बनाने वाले करुण नायर को वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम में जगह नहीं दी गई है। इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके थे। दूसरी ओर, सरफराज खान को एक बार फिर टेस्ट टीम में जगह नहीं दी गई है।

एशिया कप के फाइनल में 41 साल में पहली बार भिड़ेंगे भारत-पाक

दुबई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर एशिया कप 2025 के फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब उसका सामना खिताबी मुकाबले में भारत से होगा। यह मैच 28 सितंबर यानी रविवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम पर ही खेला जाएगा। गुरुवार को खेले गए सुपर-4 मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम निर्धारित ओवरों में नौ विकेट पर 124 रन ही बना पाई। पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने तीन-तीन विकेट झटके जबकि सैम अयूब को दो सफलताएं मिलीं। बता दें एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी। 2016 में पहली बार यह टूर्नामेंट टी20 प्रारूप में खेला गया। दिलचस्प बात यह है कि एशिया कप के 41 साल के इतिहास में कभी भी भारत-पाकिस्तान का फाइनल में आमना-सामना नहीं हुआ था।

कांग्रेस ने भाजपा पर फोड़ा लद्दाख हिंसा का ठीकरा

» आप व नेकां ने भी केंद्र सरकार को घेरा
» छठी अनुसूची की मांग को बताया जायज
» केंद्र की नीतियों ने लद्दाख को हिंसा की आग में झोंक दिया : पवन खेड़ा

4पीएम न्यूज नेटवर्क

श्रीनगर। लद्दाख में जेन जी के आंदोलन व हिंसा के बाद सियासी वार-पलटवार शुरू हो गया है। जहां कांग्रेस ने भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया है वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के ऊपर ठीकरा फोड़ा है। इस बीच गृहमंत्रालय ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

वहीं वांगचुक ने एनडीए सरकार पर उन्हें जबरदस्ती फंसाने का अरोप लगाया है। आप व नेकां भी वांगचुक के समर्थन में आया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह संकट भाजपा की नीतियों का नतीजा है। पार्टी ने दोहराया कि लद्दाख की राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग पूरी तरह न्यायसंगत है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा- लद्दाख में हुई जानहानि बेहद दुखद है। यह सरकार की नाकाम वादों की याद दिलाती है। 2019 में संसद में कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ जो हुआ है, उसके बाद शांति स्थापित होगी, लेकिन छह साल बाद हालात और बिगड़ गए हैं। केंद्र की नीतियों ने न सिर्फ घाटी बल्कि

जम्मू और लद्दाख को भी हिंसा की आग में झोंक दिया है। लद्दाख की पहचान और गरिमा की मांग को उपेक्षा नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और नेतृत्व से जवाब मिलना चाहिए।

सोनम वांगचुक की संस्था का लाइसेंस रद्द

केंद्र सरकार ने लद्दाख के जाने-माने पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के नेतृत्व वाली संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत मिला लाइसेंस रद्द कर दिया है।सरकार के आदेश के अनुसार, संस्था अब विदेश से चंदा या किसी भी तरह की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगी। लाइसेंस रद्द किए जाने के पीछे क्या कारण हैं, इस बारे में फिलहाल आधिकारिक तौर पर विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है।

हिंसा और मौतों की निष्पक्ष जांच हो : मो. हनीफा

लद्दाख से सांसद मोहम्मद हनीफा ने प्रदर्शनकारी युवकों की मौत के मामले में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को राहत देने और मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। केडीए के को-चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई ने भी लेह हिंसा समेत प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की। उन्होंने लद्दाख प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप जड़ा।

हिंसा के बाद लेह में कर्फ्यू एक दिन और बढ़ा

आंदोलन के बाद लेह में तनावपूर्ण शांति रही। यहां कर्फ्यू के एक दिन और बढ़ा दिया गया है। 26 सितंबर को भी स्कूल-कॉलेज सब बंद रहेंगे। कारगिल भी बंद रहा। इस बीच गृह मंत्रालय की एक टीम ने लेह पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की। टीम ने लेह एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय सांसद को दिल्ली बुलाया है, जहां 27-28 सितंबर को उनकी बैठक होगी और स्थानीय हितों से जुड़ी मांगों पर चर्चा की जाएगी। इस बीच लेह में किसी अप्रिय स्थिति की आशंका के मद्देनजर 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

लद्दाख में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करें : एलजी

उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक कर लेह में हालात की समीक्षा की। उन्होंने विरोध-प्रदर्शन के बाद लद्दाख में पैदा हुई स्थिति का आकलन किया। एलजी ने अधिकारियों को लद्दाख में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। यह भी कहा कि हालात को देखते हुए सतर्कता बरतते हुए एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाए।

लद्दाख में हिंसा भड़कने के पीछे वांगचुक जिम्मेदारः गृह मंत्रालय

में गृह मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था। हिंसक घटनाओं के बीच, उन्होंने अपना उपवास तोड़ा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यापक प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए।

सरकार तलाश रही बलि का बकरा, मुझे जेल भेजने की तैयारी : वांगचुक

लद्दाख में भड़की हिंसा पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो सरकार की दिक्कतें उनकी आजादी से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। वांगचुक ने गुरुवार को गृहमंत्रालय के उस बयान को खारिज किया जिसमें बुधवार की हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार बलि का बकरा तलाश रही है जबकि असली समस्या को नजरअंदाज कर रही है। मैं देख रहा हूं कि पीएसए (जनसुरक्षा कानून) के तहत मुझे दो साल के लिए जेल भेजने की तैयारी हो रही है। मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन याद रखिए, जेल में सोनम वांगचुक सरकार के लिए बाहर के वांगचुक से कहीं ज्यादा परेशानी का सबब बनेगा।

केंद्र लचीला रुख अपनाए : डॉ. जफर अखून

लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी एलएएचडीसी, कारगिल के चेयरमैन डॉ. जफर अखून ने बंद शांतिपूर्ण गुजरने पर राहत जताई। उन्होंने एक बार फिर केंद्र से लद्दाख के मामले में अपना रुख लचीला रखने और बातचीत शुरू करने की बात दोहराई। उन्होंने छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को जायज बताते हुए कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द बात शुरू करना बेहद जरूरी है।

देश का सोचने वाले सोनम वांगचुक को क्यों परेशान कर रही सरकारः केजरीवाल

» केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी बेहद घटिया राजनीति कर रही

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक पर लगे आरोपों की निंदा की और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपनी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए कर रही है जो देश की प्रगति के बारे में सोच रहा है।

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा, सोनम वांगचुक के बारे में पढ़िए। जो व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है, नए आविष्कार करता है, उसे आज केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी बेहद घटिया राजनीति के तहत परेशान कर रही है। पोस्ट में लिखा गया है कि यह बेहद दुखद है - देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में कैसे है। ऐसा देश कैसे तरक्की करेगा? यह लद्दाख में अशांति के बाद आया है, जिसके बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 14 दिनों की भूख हड़ताल की, जो पाँच साल से इन माँगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ तक कि लेह से दिल्ली तक एक उल्लेखनीय नंगे पाँव पदयात्रा भी की थी। लेह में अशांति राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही माँगों से उपजी है। जम्मू और कश्मीर के लोग भी 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से राज्य के दर्जे की इसी तरह की माँग कर रहे हैं। लेह में अधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगा दिए हैं।

केंद्र सरकार लेह के साथ प्रदेश की जनता की तरफ ध्यान दे : उमर

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लेह की जनता को नकारा गया जिसका परिणाम बुधवार को वहां हिंसा के रूप में देखने को मिला। केंद्र सरकार को लेह के साथ प्रदेश की जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा के नेता लेह में हुई हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं लेकिन अगर लेह में कांग्रेस इतनी मजबूत होती तो काउंसिल उन्हीं की बनती। स्थिति को संभालना सरकार का काम होता है। वे हमेशा अपना कसूर नहीं मानते और दूसरे को दोषी ठहराते हैं। उन्होंने लेह के लोगों से अपील की कि वे कानून को अपने हाथों में नहीं लें और आपसी भाईचारा व शांति बनाए रखें।

मुख्तार के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से राहत

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत की शर्तें हटा दी हैं। अब्बास अंसारी इस राहत के बाद यूपी से बाहर जा सकेंगे। अदालत ने कहा कि अंतरिम ज़मानत देते समय याचिकाकर्ता पर लगाई गई शर्त संख्या 6(111) में ढील दी जाती है और याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश से बाहर यात्रा करने की अनुमति है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दिलचस्प टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि अंसारी को चुप कराने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि हम अदालत को सोशल मीडिया पर हमले से बचाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कहा कि अब्बास अंसारी सार्वजनिक रूप से बोल सकते हैं या नहीं? जब अंसारी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अंसारी पर लगाई सार्वजनिक बयान न देने की शर्त में भी ढील देने का अनुरोध किया।

लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल का किया गठन

4पीएम न्यूज नेटवर्क

पटना। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा गया है और इसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पार्टी का पोस्टर भी शेयर किया है। तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा, हम बिहार के समग्र विकास के लिए पूरी तरह समर्पित और तत्पर हैं।

हमारा उद्देश्य बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाकर एक नई व्यवस्था स्थापित करना है। बिहार के समग्र विकास के लिए हम लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। पार्टी के पोस्टर में तेज प्रताप ने पाँच प्रमुख नेताओं और हस्तियों को भी शामिल किया है। पोस्टर में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर को दिखाया गया है। गौरतलब है कि तेज प्रताप ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव

को पोस्टर में शामिल नहीं किया है।

तेज प्रताप यादव की नई पार्टी के पोस्टर पर लिखा है- जनशक्ति जनता दल, सामाजिक न्याय - सामाजिक अधिकार - सम्पूर्ण परिवर्तन। जनता की शक्ति, जनता का शासन - तेज प्रताप बिहार का विकास सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही, जनशक्ति जनता दल से जुड़ने के इच्छुक लोगों के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। तेज प्रताप ने दावा किया है कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव महुआ विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे।

पटाखों पर पूरा बैन लगाना संभव नहीं : सुप्रीम कोर्ट

बोली शीर्ष अदालत- पटाखा निर्माताओं को काम करने का अधिकार है तो नागरिकों को भी सांस लेने का अधिकार है

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन पर शीर्ष अदालत ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पटाखों पर पूरा बैन लगाना संभव नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है।

हालांकि कोर्ट ने कहा कि हमें माफिया से भी सावधान रहने की जरूरत है, जो बैन के बाद सक्रिय हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पटाखा निर्माताओं को काम करने का अधिकार है तो नागरिकों को भी सांस लेने का अधिकार है। सुनवाई के दौरान सीजेआई बी आर गवई ने कहा कि अगर कोई पटाखा निर्माता नियमों का पालन करता है तो उन्हें पटाखों के निर्माण की अनुमति देने में क्या समस्या है? कोर्ट ने कहा कि इसका समाधान तो होना ही चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि अतिवादी आदेश समस्याएं पैदा करेंगे। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इसके अलावा सोशल मीडिया पर हमें अपनी बातों में सावधानी बरतने की भी जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि देशभर के मजदूर श्रमदान करते हैं, अगर मुआवजा देने का आदेश भी दिया जाता है तो ऐसी दलीलें दी जाती हैं कि मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसलिए उन्हें पटाखा बनाने दें और अगले आदेश तक एनसीआर में बिक्री न होने दें।

कोर्ट ने मांगा अंडरटेंकिंग

चीफ जस्टिस बी आर गवई ने नीरी और पीईएसओ द्वारा ग्रीन पटाखों के लिए परमिट वाले निर्माताओं को पटाखों के निर्माण की इजाजत दे दी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो अंडरटेकिंग दें कि अगली तारीख तक वे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने स्पष्ट किया है कि पूर्ण प्रतिबंध के आदेश के बावजूद, प्रतिबंध लागू नहीं हो सका, जैसे बिहार राज्य में खनन पर प्रतिबंध तो था, लेकिन इससे अवैध खनन माफियाओं को बढ़ावा मिला इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक **संजय शर्मा** द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। **महाराष्ट्र कार्यालय**:- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। **संपादक** - संजय शर्मा, **विधि सलाहकार**: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, **वित्तीय सलाहकार**: संदीप बंसल, **कार्टूनिस्ट**: हसन जैदी, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com |
website: www.4pm.co.in | **RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020** *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।